

प्रेषक,

डा० रणबीर सिंह

सचिव,

उत्तराखण्ड शासन।

सेवा में,

(1) आयुक्त,

खाद्य एवं नागरिक आपूर्ति विभाग,
उत्तराखण्ड, देहरादून।

(3) संभागीय खाद्य नियंत्रक

गढ़वाल संभाग, देहरादून/
कुमायूं संभाग, हल्द्वानी।

(2) रामस्त जिलाधिकारी,

उत्तराखण्ड।

(4) समस्त जिला पूर्ति अधिकारी,

उत्तराखण्ड।

खाद्य एवं नागरिक आपूर्ति अनुभाग-२

अक्टूबर
देहरादून: दिनांक ०७ सितम्बर, २००८.

विषय:-लक्षित सार्वजनिक वितरण प्रणाली के अन्तर्गत ए०पी०एल० योजना में माह

अक्टूबर, २००८ से दिसम्बर, २००८ तक गेहूं का तदर्थ/अतिरिक्त आवंटन।

महोदय,

जपर्युक्त विषयक अवर सचिव, सम्प्रभोक्ता मामले, खाद्य और सार्वजनिक वितरण मंत्रालय, भारत सरकार के पत्र संख्या १-७/२००८-वीपी-३। दिनांक ३० रितावर, २००८(छायाप्रति संलग्न) द्वारा लक्षित सार्वजनिक वितरण प्रणाली के अन्तर्गत उत्तराखण्ड राज्य की ए०पी०एल० योजना में माह अक्टूबर, २००८ से दिसम्बर, २००८ के लिए प्रतिमाह १२००० ग्री०टन (वारह हजार ग्री०टन मात्र) गेहूं का तदर्थ/अतिरिक्त आवंटन किया गया है।

२. इस संबंध में मुझे यह कहने का निदेश हुआ है कि भारत सरकार द्वारा उत्तराखण्ड राज्य को आवंटित गेहूं की मात्रा को जनपदवार ए०पी०एल० राशन कार्ड धारकों की संख्या के आधार पर संलग्न ब्रेकअप के अनुसार आवंटित किया जा रहा है। आप कृपया तदनुसार जनपदों को गेहूं रामयवद्ध रूप से उपलब्ध कराया जाना सुनिश्चित करने का कार्य करें।

३. माह अक्टूबर, २००८ हेतु खाद्यान्न की उठान की वैधता अवधि भारत सरकार के पत्र दिनांक ३०, सितम्बर २००८ से ५० दिन की है, अतएव कृपया निर्धारित समयावधि के भीतर आवंटित खाद्यान्न की मात्रा का भुगतान/उठान एवं वितरण सुनिश्चित किया जाये।

४. यह भी सुनिश्चित किया जाय, कि आवंटित एपीएल गेहूं लक्षित सार्वजनिक वितरण प्रणाली के निर्धारित प्रक्रिया के मानकों/नियमों के अन्तर्गत वितरण किया जाय, तथा पूर्ण सतर्कता वरती जाय कि आवंटित खाद्यान्न का लीकेज/डाईवर्जन कदापि न हो। भारत सरकार के आदेश संख्या-४-७/२००५ PY IV/PD-I(Pt) दिनांक १७ जनवरी, २००८ के अनुपालन करते हुए लक्त ए०पी०एल० गेहूं रास्कारी राते गल्ले की दुकान के माध्यम से नियमानुसार वारतविक राशन कार्ड धारकों को उपलब्ध कराया जाय, जिरामें संवंशित अधिकारी का पूर्ण दायित्व रहेगा।

5. इस संबंध में शासन द्वारा समय-समय पर निर्गत शासनादेशों का अनुपालन कड़ाई रो किया जाय।

6. आवंटित ए०पी०एल० गेहूँ का भौतिक सत्यापन के साथ उपयोगिता प्रमाण पत्र शासन को निर्धारित समयसीमा में उपलब्ध कराया जाये।

भवदीय,

/
(डॉ रणबीर सिंह)

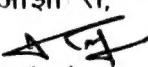
सचिव।

संख्या ५२७(१)/०८-XIX-२/१११ खाद्य/२००२ तददिनांक।

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित:-

1. आयुक्त, गढ़वाल मण्डल पौड़ी/कुमायू मण्डल, नैनीताल।
2. उप सचिव,(बीपी) उपभोक्ता मामले, खाद्य और सार्वजनिक वितरण मंत्रालय, भारत सरकार नई दिल्ली को उनके पत्र संख्या १-७/२००८-बीपी-III दिनांक ३० सितम्बर, २००८ के संदर्भ में।
3. वरिष्ठ क्षेत्रीय प्रबन्धक, भारतीय खाद्य निगम, उत्तराखण्ड, देहरादून।
4. वित्त नियंत्रक, खाद्य एवं नागरिक आपूर्ति, विभाग, उत्तराखण्ड, देहरादून।
5. वरिष्ठ संभागीय वित्त अधिकारी, (खाद्य), गढ़वाल संभाग, देहरादून/कुमायू संभाग, हल्द्वानी।
6. अपर सचिव, मुख्यमंत्री को मा० मुख्यमंत्री जी उत्तराखण्ड के अवलोकनार्थ निजी सचिव, खाद्य मंत्री उत्तराखण्ड को मा० मंत्री जी के अवलोकनार्थ।
7. निजी सचिव, मुख्य सचिव, उत्तराखण्ड शासन को मुख्य सचिव महोदय के अवलोकनार्थ।
8. समन्वयक, एन०आई०सी०, उत्तराखण्ड, देहरादून।
9. गार्ड फाईल।

आज्ञा/से,


(हरिओम)

संयुक्त सचिव।

वर्ष 2008 में माह अक्टूबर, 2008 से दिसम्बर, 2008 हेतु तदर्थ/अतिरिक्त
ए०पी०एल० गेहूं का माहवार/जनपदवार आवंटन

शासनादेश सं०-५२७०८-XIX-२/१११-खाद्य/०२ टी०सी, दिनांक ०७ अक्टूबर, 2008 का संलग्नक

ए०पी०एल० योजना

(मी०टन में)

गढ़वाल संभाग

क०सं०	जनपद का नाम	गेहूं का आवंटन
1.	देहरादून	2196.000
2.	हरिद्वार	1703.400
3.	पौड़ी गढ़वाल	1119.900
4.	ठिहरी गढ़वाल	713.400
5.	चमोली	498.100
6.	रुद्रप्रयाग	338.200
7.	उत्तरकाशी	367.800
	योग:-	6936.800

कुमायू संभाग

8.	नैनीताल	1313.700
9.	बागेश्वर	298.200
10.	पिथौरागढ़	594.600
11.	चम्पावत	285.100
12.	ऊधमसिंह नगर	1745.900
13.	अल्मोड़ा	825.700
	योग:-	5063.200
	महायोग:-	12000.000

(हरिओम)
संयुक्त सचिव।